

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 अप्रैल 2012

विषय:- मै0सक्सैना हैल्थ केयर, गुडगांव हरियाणा को ग्राम सरकड़ा, तहसील सितारगंज जिला उधमसिंहनगर में फार्मास्यूटिकल्स उद्योग हेतु 0.158 है0भूमि क़य की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-783/सात-स0भू0अ0/2010 दिनांक 16 फरवरी, 2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-231/भू0कय/18(1) /2006 दिनांक 20 मार्च, 2008 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, मै0 सक्सैना हैल्थ केयर, गुडगांव हरियाणा को फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम सरकड़ा के खसरा नं0-304 मध्ये रकबा 0.158 है0 भूमि क़य की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क़ेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क़य करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क़ेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क़ेता द्वारा क़य की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (फार्मास्यूटिकल्स उद्योग की स्थापना हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क़य किया गया था उससे भिन्न

24

प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क़य से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि क़य की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- क़य की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन हेतु, फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- ईकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व, विभिन्न विभागों से वांछित अनुज्ञा, अनापत्ति/सहमति यथा-ड्रग कन्ट्रोलर से ड्रग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, जिला प्रशासन तथा राज्य व केन्द्रीय कानूनों के तहत, अपेक्षित स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

9- ईकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में, उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क़य के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

11- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

14- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

15- प्रश्नगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क़य व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है और पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता

स्वतः निर्धारित नहीं करती है जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

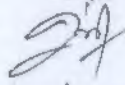
(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पू0प0सं0-760 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- डा0 सुब्रत सक्सेना, नि0 135 पी. सैक्टर 56 गुडगांव, हरियाणा।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।